INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा हेतु

HANDWRITTEN NOTES

[भाग -3]

भारत + विश्व + राजस्थान की अर्थव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 3

भारत + विश्व + राजस्थान की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें **/***

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp Link- https://wa.link/uwc5lp

Online Order Link- https://bit.ly/3X6MGue

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम (2023)**

क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणायें • सामान्य परिचय • प्रकार • शाखाएं • महत्वपूर्ण प्रश्न	1-5
2.	बजट • बजट निर्माण • बजटीय प्रवृत्तियां • जीरो बेस बजट • जेंडर बजटिंग • बजट 2022-23 • बजट 2023-24 • महत्वपूर्ण प्रश्न	6-23
3.	बैंकिंग • मौद्रिक प्रणाली (साख नियंत्रण) • विभिन्न दरें • बैंकों का वर्गीकरण एवं उनके कार्य • Non Performing Assets (NPA) • वित्तीय समावेशन	24-49

	• महत्वपूर्ण प्रश्न	
4.	लोक वित्त • भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व • महत्वपूर्ण प्रश्न	50-55
5.	भारत में कर सुधार ○ वस्तु एवं सेवा कर ○ महत्वपूर्ण प्रश्न	56-61
6.	राष्ट्रीय आय • GDP, NDP, GNP, NNP • राष्ट्रीय आय की माप • केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) • महत्वपूर्ण प्रश्न	61-70
7.	संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान • आर्थिक संवृद्धि	70-72
8.	लेखांकन – अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग	72-83
9.	स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार • महत्वपूर्ण प्रश्न	83-90
10.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ	90-94

11.	सब्सिडी एवं लोक वितरण प्रणाली • सब्सिडी के प्रकार, फायदे, नुकशान • PDS , राष्ट्रीय खाध्य सुरक्षा अधिनियम • ऑपरेशन ब्लैक	94-105
12.	ई-कॉमर्स • प्रकार ,फायदे, नुकशान • महत्वपूर्ण प्रश्न	105-111
13.	मुद्रास्फीति • अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र • WPI, CPI • मुद्रास्फीति पर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव • मुद्रास्फीति के प्रभाव • मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय • कीमतें, मांग और पूर्ति प्रबंधन • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	112-125
14.	केंद्र – राज्य वित्तीय संबंध • नवीनतम वित्त आयोग • राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	125-130
15.	कृषि	131-157

	• कृषि के प्रकार • प्रमुख फसलें, हरित क्रांति, सिंचाई • भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन • कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
16.	औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां • औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त • प्रमुख उद्योग • उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण • आर्थिक सुधार एवं आर्थिक वृद्धि • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	158-181
17.	भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र • प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र	182-183
18.	आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका • विभिन्न कार्यक्रम • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	184-188
19.	आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहलें • पंचवर्षीय योजनायें	188-196
20.	मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास • मानव विकास सूचकांक	197-201

	• वैश्विक खुशहाली सूचकांक • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
21.	गरीबी एवं बेरोजगारी एवं असमानता • बेरोजगारी के कारण, प्रभाव, सरकार की पहलें • गरीबी का मापन • गरीबी से सम्बंधित विभिन्न समितियां • स्वास्थ्य सेवा और नयी शिक्षा नीति • आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	202-222
22	केंद्र सरकार की योजनाएँ • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान	223-227
	वैश्विक अर्थव्यवस्था	
1.	वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां • विश्व बैंक • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) • विश्व व्यापार संगठन • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	228-238
2.	सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	238-242

	राजस्थान की अर्थव्यवस्था	
1.	अर्थव्यवस्था का वृहद् परिदृश्य • बजट 2023 – 24 के अनुसार	243-254
2.	कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे • डेयरी और पशुपालन • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	254-262
3.	ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना • पंचायती राज • वित्त आयोग • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	263-273
4.	औद्योगिक विकास, वृद्धि • पंचवर्षीय योजनायें • खादी और ग्रामोद्योग • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	273-289
5.	संवृद्धि, विकास एवं आयोजना • परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	289-291
6.	आधारभूत अवसंरचना एवं संसाधन • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	291-298

7.	प्रमुख विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं • राजस्थान का बजट 2023–24 • राज्य आर्थिक समीक्षा 2023–24 • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	298–339
8.	बुनियादी सामाजिक सेवाएं • शिक्षा व स्वास्थ्य • गरीबी एवं बेरोजगारी • सतत विकास लक्ष्य • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	339–361

अर्थशास्त्र

अध्याय – I

अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणायें

परिचयः-

- Economics (अर्थशास्त्र) शब्द एक Greek word ' Oikonomia ' से उत्पन्न हुआ है ।
- Oikonomia शब्द Oikos and Nomos दो शब्दों से मिलकर बना है ।
- Oikos का अर्थ गृह अथवा परिवार जबकि Nomos का का अर्थ है प्रबंधन । अर्थात् Oikonomia गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है ।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर?:-

अर्थशास्त्र	अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है	अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है	अर्थव्यवस्था निष्पादन (Execution) की भूमिका निभाती है।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है इनकी किताब (The Wealth of nations) मे अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है।	जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं ।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं- (i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics) (ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)	अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
	अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economic)

- अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)

(ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

अर्थव्यवस्था के प्रकारः-

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy):-

- जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
- अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है।
- एडम स्मिथ की 'दा वेल्थ ऑफ़ नेशन' पूँजीवाद को दार्शनिक आधार प्रदान करता है।
- अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देश पूँजीवाद के समर्थक हैं।

पूँजीवाद के फायदे या गुणः-

- पूँजीवाद नवाचार को बढ़ावा देता है।
- पूँजीवाद और समाज दोनों स्वतंत्रता और अवसर पर केंद्रित हैं।
- पूँजीवाद आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
- पूँजीवाद स्व-नियामक है।
- पूँजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद करता है।

पूँजीवाद के नुकसान या दोषः-

- धन और आय के वितरण की असमानता
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य के रूप में कक्षा संघर्ष
- सामाजिक लागत बहुत अधिक है
- पूँजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता
- बेरोजगारी और रोजगार के तहत

- वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है ।

B. समाजवाद अर्थव्यवस्था

- उत्पादन एवं वितरण के सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है।
- राज्य द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र की भूमिका से लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति।
- भारत,बांग्लादेश,ब्राजील,समेत विकासशील अधिकांश देश समाजवाद के समर्थक हैं।
- बौद्ध और जैन धर्म का अस्तेय आवश्यकता से अधिक संसाधनों के एकत्रीकरण का विरोध करता है, जो समाजवाद की अवधारणा के अनुकूल है।
- अशोक के शिलालेखो से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती हैं, वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में प्रमाण देता है।
- इसी प्रकार मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण, बेरोजगारों के लिए पेंशन जैसी समाजवादी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

समाजवाद के पक्ष में तर्क या गुणः-

शोषण का अन्तः-

- समाजवाद श्रमिको एवं निर्धनो के शोषण का विरोध करता है। इसलिये विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते है।

सामाजिक न्याय पर आधारितः-

- समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितो को महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितो को महत्व दिया जाता है यह व्यवस्था पूँजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करती है जिसमें विषमता न्यनूतम हो।

उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यक्ताः-

- व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में समाजिक आवश्यक्ता और हित को ध्यान में रखकर उत्पादन होगा क्योंकिसमाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसख्यक लोगो के लाभ के लिए हो।

उत्पादन पर समाज का नियंत्रण :-

- समाजवादियो का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनो पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है।
- सभी को उन्नति के समान अवसर
- साम्राज्यवाद का विरोधी

समाजवाद के विपक्ष में तर्क अथवा आलोचना :-

राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि :-

- समाजवाद मे आर्थिक तथा राजनीतिक दोनो क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और समपादित नहीं होंगे।

वस्तुओं के उत्पादन में कमी :-

- समाजवाद के आलोचको की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनो पर सम्पूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी और कार्यक्षमता भी धीरे धीरे घट जायेगी।
- व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जायेगी।

समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी :-

- प्रजातंत्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है वही समाजवाद में वह राज्य रूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पूर्जा बन जाता है।

नौकरशाही का महत्व :-

- समाजवाद में राज्य के कार्यो में वृध्दि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता है। और सभी निर्णय सरकारी कर्मचारियो द्वारा लिये जाते है ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता है।

समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है :-

- समाजवाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक मार्ग को अपनाता है। वह शांतिपूर्ण तरीको में विश्वास नहीं करता।
- वह वर्ग संघर्ष पर बल देता है। जिसके परिणामस्वरूप समाज में वैमनस्यता और विभाजन की भावना फैलती है।
- पूर्ण समानता संभव नहीं ।

अध्याय - 2

बजट

बजट

- बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को कहा जाता हैं।
- लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, वित्तीय व्यवस्था। शासन द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती हैं। यह धन कहाँ से आयेगा? और यह धन कहाँ-कहाँ खर्च होगा? यह सभी बातें सुविचारित तथा सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इसी व्यवस्था को बजट के नाम से जाना जाता हैं।

बजट का अर्थ

- स्पष्ट हैं कि शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को बजट कहा जाता हैं। यह लेखा एक वर्ष का हो सकता हैं या उससे अधिक वर्ष का भी हो सकता हैं। इस लेखे में वर्ष में विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का वर्णन रहता हैं, साथ ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी रहता हैं कि उसके लिए जरूरी धन कहाँ से आयेगा? नये करों का प्रावधान भी उसमें रहता हैं।

एक अच्छे बजट के मुख्य लक्षण या विशेषताएं

1 बजट एक निश्चित अवधि के लिए आय-व्यय का अनुमान हैं।

2 यह एक तुलनात्मक तालिका भी हैं, जिसमे प्राप्तियों व खर्चों की राशियों की तुलनात्मक विवेचना होती हैं।

3 यह सरकार के लिये धन उगाही और व्यय के लिये विधायिका का आदेश हैं।

4 यह प्रशासन के कार्यों का वित्तीय प्रतिवेदन हैं।

बजट के प्रकार (Types Of Budget)

(1) निर्माण के आधार पर (On the Basis of Construction):

i व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित बजट ।

ii कार्यपालिका द्वारा निर्मित बजट (भारत में यही प्रचलित हैं) ।

iii मण्डल या आयोग द्वारा निर्मित बजट (अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित हैं) ।

(2) स्वरूप के आधार पर (On the Basis of Format):

(A) लाइन आइटम बजट (Line-Item Budget):

यह बजट का परम्परागत रूप हैं । यह 18वीं-19वीं सदी में विकसित हुआ । इस बजट में वस्तुओं या मद का महत्व अधिक होता हैं । उन मदों या वस्तुओं पर खर्च से क्या उद्देश्य हासिल होगा, इस पर नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य अपव्यय, अधिक खर्च और बर्बादी को रोकना हैं ।

i. लाइन-आइटम बजटिंग में सार्वजनिक व्यय पर कठोर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य को प्रमुखता दी जाती हैं । इसमें बजट को सार्वजनिक खर्च पर नियन्त्रण रखने की विधि के रूप में देखा जाता हैं जिसका परिणाम वस्तुनिष्ठ बजट के रूप में सामने आता हैं ।

ii. इसमें व्यय की प्रत्येक मद को पंक्तिवार (लाइन) लिखा जाता हैं ।

iii. इसमें यह देखा जाता हैं कि जिस मद पर खर्च की स्वीकृति हुई हैं, वह उसी पर व्यय हो, यद्यपि लाइन आइटम बजट को इस वस्तुनिष्ठता के बजाय एक दूसरे रूप में भी बनाया जाता हैं । जिसमें एक मद का पैसा दूसरे मद में भी खर्च करने की अनुमति रहती हैं।

iv. इसमें खर्च की जाने वाली राशि पर जोर अधिक रहता हैं, उससे क्या परिणाम हासिल हुआ, उस पर नहीं ।

v. इसे अभिवर्धन बजट व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि बजट राशि सदैव पूर्व की अपेक्षा अधिक दी जाती हैं । वैसे यही बजट अन्य सुधारात्मक बजट जैसे शून्य बजट आदि का आधार होता हैं।

(B) कार्य निष्पादन बजट (Performance Budgeting):

- यह वर्ष 1930 की मंदी का परिणाम था ।
- सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुवर आयोग (1949) ने इसकी सिफारिश की थी और 1950 में राष्ट्रपति ट्रुमेन ने इसे अपनाया था ।
- निष्पादन बजट (Performance Budget) शब्दावली सर्वप्रथम हुवर कमीशन (1949) ने ही प्रयुक्त की थी ।
- हुवर आयोग ने कार्य, कार्यक्रम और क्रिया को बजट का आधार बनाने की सिफारिश की थी, जो कार्य निष्पादन बजट के 3 प्रमुख तत्व हैं ।

- यह बजट व्यय को सीधे उपलब्धियों से जोड़ देता है । यह व्यय के स्थान पर व्यय के उद्देश्य पर आधारित है । इससे बजट का स्वरूप लोकतांत्रिक हो जाता है । सरकारी गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं । व्यवस्थापिका को स्पष्ट हो जाता है कि सरकार कौन से कार्यक्रम या परियोजनाएं शुरू कर रही है । इससे अगले वर्ष इनकी प्रगति के बारे में वह प्रभावशाली ढंग से पूछ सकती है ।
- यह नवीन लोक प्रशासन की देन है और वित्तीय प्रशासन में सुधार का आवश्यक अंग है । इसे शुरुवात में कार्यात्मक बजट या गतिविधि-बजट कहा जाता था ।

भारत का बजटीय इतिहास

- बजट शब्द का प्रतिपादन फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुआ है , जिसका अर्थ चमड़े का बैग होता है ।
- वर्ष 1733 ई . में इंग्लैण्ड में इस शब्द का प्रयोग जादू के पिटारे के अर्थ में किया गया था ।

- ***भारत में बजट निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है ; जैसे***

✓ विगत वित्त वर्ष के वास्तविक आय - व्यय अनुमान
✓ चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान
✓ चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान
✓ आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान

- ***भारत के बजटीय इतिहास के निम्नलिखित प्रमुख तथ्य***

➢ स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर , 1947 को पहले वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम द्वारा पेश किया गया था ।
➢ जॉन मेथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था ।
➢ गैर - हिन्दी भाषी होने के बावजूद सीडी देशमुख ने वित्तमंत्री रहते सुनिश्चित किया था कि बजट के सभी दस्तावेज हिन्दी में भी छपे । इससे पूर्व वे केवल अंग्रेजी में ही छपते थे
➢ मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह , विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश में चार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं , जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके । भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे , उन्होंने कुल दस बजट पेश किए , जबकि पी . चिंदबरम ने अब तक आठ बजट पेश किए हैं ।
➢ हेमवती नन्दन बहुगुणा , के.सी. नियोगी और मनमोहन सिंह वित्तमंत्री रहने के बावजूद भी बजट पेश नहीं कर पाए ।
➢ अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया जो उसके लिए शाम के पाँच बजे का समय रखा गया था , लेकिन वर्ष 1999 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया ।
➢ 25 फरवरी , 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी , 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था ।
➢ सर्वप्रथम सर्विस टैक्स की शुरुआत वर्ष 1994-95 के बजट की गई । इस समय पहली बार टेलीफोन बिल , स्टॉक ब्रेकिंग चार्ज एवं जनरल इंश्योरेंस पर 5 % सर्विस टैक्स लगाया गया था ।

बजट निर्माणकारी एजेंसियाँ

- बजट का निर्माण एक व्यापक कार्य है , एक संस्था नहीं बल्कि अनेक संस्थाएँ मिलकर कार्य करती हैं , जिनका विवरण निम्नलिखित है-
- ***योजना आयोग-*** बजट निर्माण में प्रमुख भूमिका यद्यपि वित्त मंत्रालय की होती है , लेकिन योजना हेतु कितने संसाधनों की व्यवस्था तथा संसाधनों के व्यय संबंधी सभी बातों की जिम्मेदारी योजना आयोग के ऊपर होती थी । योजना आयोग बजट में योजनाओं की प्राथमिकता को शामिल करने का कार्य करती थी यही जिम्मेदारी अब NITI आयोग को दे दी गई है ।
- ***वित्त मंत्रालय-*** बजट के लिए जरूरी सभी संसाधनों का एकत्रीकरण , भिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापना तथा प्रारम्भिक स्तर से लेकर अन्तिम स्तर तक बजट के समस्त कार्यों का सम्पादन वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा ही किया जाता है ।
- ***प्रशासनिक मंत्रालय*** बजट के निर्माण में जरूरी सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रशासनिक मंत्रालय (Administration Ministry) करता है ।
- ***नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक*** - बजट निर्माण के समय आवश्यक कुशलता की पूर्ति कैग (

बजट 2023-24

2023-24 का बजट अनुमान

- कुल प्राप्तियां (उधारी के अलावा)- 27.2 लाख करोड़
- कुल व्यय - 45 लाख करोड़
- नेट टैक्स प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़

बजट 2023 की खास बातें

- भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 रु. हुई।
- अगले एक साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी।
- पीएम सुरक्षा के तहत् 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा।
- बागवानी योजनाओं पर रहेगा जोर, 2200 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान।
- कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड रुपए किया जाएगा।
- 157 नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग हिस्सों में खोले जाएंगे।
- अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ खर्च होंगे।
- पीएम आवास योजना फंड में 66 फीसदी की बढ़ोतरी।

बजट 2023 में क्या हुआ सस्ता और महंगा?

- सस्ता - इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, साइकिल, लिथियम बैटरी, हीरे के आभूषण।
- महंगा:- सोना, आयातित चाँदी, प्लेटिनम, विदेशी किचन चिमनी, सिगरेट।

Note:- 2023-24 का बजट अमृत काल में पहला बजट है।

- बजट: व्यय, कर, लेन- देन और योजनाओं का ब्लूप्रिंट है।
- संविधान के अनुच्छेद- 112 में बजट शब्द का उपयोग न करते हुए इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है।
- यह बजट आगामी वर्ष 2023- 24 के लिए पेश किया गया है।
- वर्ष 2022- 23 में भारत की विकास दर 7% के आस-पास रही है, जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसी महामारी कोविड-19 और वैश्विक मंदी जो रही है।
- वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा गया था। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही है।
- वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत रखा गया है और इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2023-24 का बजट 7 मूल आधारों पर आधारित है, जिसे सप्त ऋषि- 7 कहा गया है।

1. समावेशी विकास - (a)कृषि (b)स्वास्थ्य क्षेत्र (c)शिक्षा क्षेत्र
2. वित्तीय क्षेत्र
3. युवा शक्ति
4. आखिरी व्यक्ति तक पहुंच
5. अवसंरचना निवेश
6. सक्षमता का विकास
7. हरित विकास

कृषि और सहकारिता:- ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि

- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम
- भारत को श्री अन्न देने के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
- पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य।
- भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग।
- भारत मिलेट (बाजरा) को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है।

❖ **स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि:-** वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत।

- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए **उन्मूलन मिशन** की शुरुआत।

- चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहन।
- फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत।

❖ **आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना** : "कोई पीछे न छूटे"

- प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत।
- कर्नाटक के सूखा संभाव्य क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता।
- 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती।
- PMGKAY के तहत, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
- प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए 'भारत श्री' योजना की शुरुआत।
- पीएम- आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि।

अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश :-

विकास व रोजगार के अवसरों में वृद्धि:

- पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हित धारकों की सहायता करेगा।
- UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी- 2 और श्रेणी- 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन।
- राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा।

Note- अमृत काल के लिए **संकल्पना:** "सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था"

- इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

1. नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।

2. विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना।

3. वृहद् आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना।

❖ **अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं -**

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:

2. पीएम- विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)

3. पर्यटन

4. हरित विकास

❖ **अध्यापकों का प्रशिक्षण:-** नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत् पेशेवर विकास, डिपास्तिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा।

- बच्चों और किशोरों के लिए **"राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तका लय"** की स्थापना की जाएगी।

❖ **अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना:** -सरकार द्वारा आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया गया है।

❖ **आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम:** - हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

❖ **एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल:-** अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा।

- **भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)** :- 'भारत साझा पुरालेख निधान' एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित।
- विकास और रोजगार के संवाहक के रूप में पूंजीगत निवेश में 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होगा।

प्रश्न.-3. जेण्डर बजट से आप क्या समझते हैं ?
प्रश्न.-4. GST परिषद् को समझाइए ।
प्रश्न.-5. जीरो बैस बजट क्या है ? इसे भारत में पहली बार कब लागू किया गया।
प्रश्न.-6. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों व लक्ष्यों पर टिप्पणी कीजिए ।
प्रश्न.-7. 15 वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर टिप्पणी कीजिए ।
प्रश्न.-8. वित्तीय समायोजन को समझाइये ?

अध्याय – 6
राष्ट्रीय आय

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों , चाहे वे निवासी हों या अनिवासी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) कहा जाता है।
- इसी प्रकार देश के सामान्य नागरिकों द्वारा विदेशों में की गई मूल्य वृद्धि संबंधित देश के सकल घरेलू उत्पाद का भाग है ।

एक देश की घरेलू सीमा

- ✓ एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित (Factor Income) को घरेलू आय (अथवा घरेलू उत्पाद) कहा जाता है । अतः हमें घरेलू सीमा की अवधारणा को अवश्य समझ लेना चाहिए ।
- ✓ आम बोलचाल की भाषा में एक राष्ट्र की घरेलू सीमा का अर्थ देश की राजनीतिक सीमाओं (Political Frontiers) के अंदर के भू - भाग (Territory) से लिया जाता है परन्तु राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है ।
- ✓ **इससे निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है**

  (1) राजनीतिक सीमाओं का भू - भाग जिसमें देश की सामुद्रिक सीमा भी सम्मिलित होती है ।

  (2) देश के निवासियों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में चलाए जाने वाले वायुयान तथा जलयान । उदाहरण के लिए , जापान तथा कोरिया के बीच नियमित रूप से चलने वाले भारतीय जलयान अथवा इंग्लैण्ड और कनाडा के बीच एयर इंडिया द्वारा चलाए जाने वाली हवाई जहाज भी भारत की घरेलू सीमा के ही अंग हैं ।
- ✓ मछली पकड़ने की नौकाएँ , तेल व प्राकृतिक गैस यान (Rigs) तथा तैरते हुए प्लेटफार्म (Floating Platforms) जो अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा में देश के निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं जिनमें दे को तेल खोजने

का एकमात्र (Exclusive) अधिकार है । उदाहरण के लिए भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने की नौकाओं को हिंद सागर के अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग में चलाना , भारत की घरेलू सीमा का अंग है । उपरोक्त नोट इस स्थिति में भी लागू होता है।

✓ एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास , वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान । उदाहरण के लिए , अमेरिका में भारतीय दूतावास , भारत की घरेलू सीमा का अंग है तथा भारत में अमेरिका का दूतावास अमेरिका की घरेलू सीमा का अंग है ।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)

- शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product) ज्ञात करने के लिए GDP में से पूँजी स्टॉक की खपत (मूल्य ह्रास) को घटाना होता है ।
- गणितीय समीकरण के रूप में , **NDP = GDP = Depreciation**
- **बाजार कीमत तथा कारक (साधन) लागत की अवधारणा**

➢ राष्ट्रीय आय / राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार कीमत अथवा कारक (साधन) लागत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है ।

➢ बाजार कीमत में व्यक्त राष्ट्रीय आय / उत्पाद (अथवा घरेलू आय / उत्पाद) को बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय (अथवा बाजार कीमत पर घरेलू आय) कहा जाता है ।

➢ इसी प्रकार , कारक (साधन) लागत के रूप में व्यक्त राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है ।

➢ इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है बाजार कीमत में दो प्रभाव सम्मिलित होते हैं –

(i) आर्थिक सहायता (Subsidies) का प्रभाव जिसके कारण बाजार कीमत घटती है । (ii) अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) का प्रभाव जिसके कारण बाजार कीमत बढ़ती है । कारक लागत , आर्थिक सहायता अथवा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव से मुक्त होती है । तदुसार बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय (अथवा घरेलू आय) को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय / राष्ट्रीय उत्पाद में बदलने के लिए निम्नलिखित समीकरण की सहायता ली जाती है

- **बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय** – अप्रत्यक्ष कर + आर्थिक = कारक लागत पर राष्ट्रीय आय
- आर्थिक सहायता जो बाजार कीमत को कम करती है इसमें जोड़ी जाती है एवं अप्रत्यक्ष कर जो बाजार कीमत को बढ़ाते हैं इसमें से घटाए जाते हैं ।
- उपर्युक्त समीकरण को निम्नलिखित ढंग से भी लिखा जाता है-

(बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = कारक लागत पर राष्ट्रीय आय)

(शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = अप्रत्यक्ष कर – आर्थिक सहायता)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गयी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है।
- इसका अनुमान घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़कर लगाया जा सकता है ।

(GNP = GDP + X – M)

जिसमें

X = देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय

M = विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय

उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि X = M है , तो GNP = GDP के होगा । इसी प्रकार जब बन्द अर्थव्यवस्था (Closed economy)) के अन्तर्गत X - M = 0 (शून्य) है तो वहाँ GNP GDP होगा।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक ज्ञात करने के लिए GNP में से पूँजी सटॉक की खपत (मूल्य ह्रास) को घटाना होता है ।

- **गणितीय समीकरण के रूप में-**

(NNP = GNP – Depreciation)

राष्ट्रीय आय (National Income)

- जब NNP का मूल्यांकन अथवा मापन साधन लागत पर किया जाता है , तो उसे ही राष्ट्रीयआय के नाम से जाना जाता है ।
- इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) में से अप्रत्यक्ष करों को घटाना होता है , जबकि सब्सिडी को जोड़ना

किसी देश ने अपनी जैव - विविधता को कितना नुकसान पहुँचाया अथवा उससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा ।

- हरित GDP की गणना सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध प्राकृतिक पूंजी की खपत के (जिसमें संसाधनों में आई कमी , पर्यावरण क्षरण एवं पर्यावरणीय संरक्षात्मक पहल शामिल होती है) मौद्रिक मूल्य को घटाकर की जाती है ।

हरित जीएनपी (Green GNP)

- एक दी हुई समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम सम्भावी मात्रा है , जो कि देश की प्राकृतिक सम्पदा को स्थिर बनाए रखते हुए प्राप्त की जा सकती है ।
- वर्ष 1995 में हरित GNP की अवधारणा का प्रारम्भ किया गया एवं इसमें अभी तक 192 देशों को शामिल किया गया है । [हरित GNP कुल वृद्धि - प्राकृतिक (पर्यावरणीय) ह्रास]

हरित सूचकांक (Green Index)

- विश्व बैंक ने देश की सम्पत्ति के आंकलन का एक नया सूचकांक विकसित किया है । इसके अन्तर्गत इसके प्रत्येक तीन अंगों उत्पादित सम्पत्ति , प्राकृतिक सम्पदा और मानव संसाधन के आधार पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है ।
- इस सूचकांक का विकास वर्ष 1995 में हुआ ।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना

- भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान वर्ष 1868 में दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ' पॉवटी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया ' में लगाया था ।
- इसके अतिरिक्त शाह और खम्बत , फिण्डले शिराज , वाडिया एवं जोशी आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था ।
- इन लोगों ने गणना के लिए कृषि क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्राप्त कर इसमें एक निश्चित प्रतिशत कृषि भिन्न क्षेत्र (Non - agri cultural Sector) के भाग के रूप में जोड़ दिया था । इन अनुमानों की मान्ताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था ।
- वर्ष 1931-32 में डॉ . वी . के . आर . वी . राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया । इसी कारण राव को " राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक " माना जाता है ।
- डॉ राव ने उत्पादन गणना प्रणाली (Calculation of Pro duction Method) और आय - गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया था ।
- स्वतंत्रता पूर्व काल में उपलब्ध आँकड़ों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए डॉ . राव का अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है । राष्ट्रीय आय समिति और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) ने डॉ . राव की पद्धति में कुछ संशोधन कर उसे स्वीकार कर लिया ।

हिन्दू वृद्धि दर (Hindu Growth Rate)

- हिन्दू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अथवा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है ।
- हिन्दू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक प्रो . राज कृष्ण थे ।
- आर्थिक सुधारों के आरम्भ होने से पूर्व 1950 के दशक के मध्य भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 3.5% थी , इस वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर को ही हिन्दू वृद्धि दर कहा गया ।
- वर्ष 1950-80 के बीच यह वृद्धि दर 3 से 4 % तक रही । पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इस 3 से 4 % वार्षिक वृद्धि दर को समाजवादी वृद्धि दर कहा ।
- वर्ष 1991 में अपनाए गए उदारीकरण की नीति के पशचात् भारत इस वृद्धि दर से बाहर निकलने में सफल रहा ।

राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ

- राष्ट्रीय आय से संबंधित भारत के महत्त्वपूर्ण संगठन निम्नलिखित हैं -

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) :

✓ 4 अगस्त , 1949 को केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता स्थित इण्डियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रो . पी . सी . महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की , जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढाँचा व केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) की स्थापना की गई।

- ✓ केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) की स्थापना की घोषणा वर्ष 1949 में की गई । इसका मुख्यालय नई दिलली में है । भारत में राष्ट्रीय आय और संबंधित सभी पक्षों की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है ।
- ✓ CSO राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों , प्राथमिक , द्वितीयक एवं तृतीयक तथा 14 उप - क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ।
- ✓ प्राथमिक क्षेत्र में कृषि , वन क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र व खाने शामिल की जाती है । द्वितीयक क्षेत्र के दो प्रमुख अंग हैं - विनिर्माण (Manu facturing) तथा निर्माण (Construction) । तृतीयक क्षेत्र में व्यापार , परिवार , संचार , बैंकिंग , स्थावर सम्पदा (Real Es tate) तथ सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ शामिल की जाती हैं ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)

- ✓ योजना तथा नीति निर्माण में उपयोग हेतु राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणों के द्वारा अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों पर आँकड़ों के संग्रह हेतु एक स्थायी सर्वेक्षण संगठन रखने के उद्देश्य से प्रो . पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आय समिति को अनुशंसाओं के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey , NSS) की स्थापना की गई ।
- ✓ राष्ट्रीय प्रतिर्दश सर्वेक्षण निदेशालय को मार्च , 1970 के सरकारी संकल्प के अनुसार , राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sampel Survey Organisation , NSSO) में पुनर्गठित कर दिया गया । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सामान्यतः एक वर्ष की अवधि (जुलाई - जून) के लगातार दौरों के रूप में संचालित किया जाने वाला एक निरन्तर सर्वेक्षण कार्यक्रम है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑफिस कहा जाता है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (National Statistical Commission)

- ✓ सी . रंगराजन समिति द्वारा वर्ष 2000 में दिए गए सुझाव के आधार पर । जून , 2005 को स्थायी सांख्यिकीय आयोग गठित किया गया ।
- ✓ 12 जुलाई , 2006 को प्रो . सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इसने (NSC) कार्य प्रारम्भ किया । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) का कार्य लगभग समाप्त होचुका है , किन्तु NSSO द्वारा आकि सर्वेक्षण का कार्य अब भी जारी है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिशें

- ✓ इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार , भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की मुख्य कमियाँ निम्नलिखित हैं-

- राज्यों के स्तर पर कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़ों के कुलक (Data sats) उपलब्ध नहीं हैं । इसमें उल्लेखनीय है - मुख्य फसलों की काश्त की लागत , औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (Index of Industrial Production) , थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांकों के आँकड़ों का उपलब्ध न होना ।
- आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक तैयार किया जाता है । परन्तु राज्यों के स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपलब्ध न होना , आंकड़ों संबंधी मुख्य कमजोरी है , जिसे दूर किया जाना चाहिए । अधिकतर राज्यों में औद्योगिक उत्पादन के आँकड़े एकत्र कर कोई आधार श्रृंखला तैयार नहीं की जाती और उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) राज्य में औद्योगिक क्रिया का एकमात्र स्रोत है । उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आँकड़े प्रत्येक वर्ष तैयार किए जाते हैं और दो वर्ष के विलम्ब के पश्चात् प्रकाशित किए जाते हैं । आयोग ने थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक के राज्य स्तर पर आंकड़े तैयार करने की सिफारिश की है और इसके अतिरिक्त निगम क्षेत्र में उद्यमों के सन्दर्भिका सर्वेक्षण भी तैयार करने की सिफारिश की है ।

भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण (Distribution of National Income in India)

- भारत में आय के वितरण की सीधी जाँच के लिए आँकड़े उपलब्ध नहीं है । सभी अध्ययनों में आयकर संबंधी आंकड़ों के अतिरिक्त पारिवारिक संरक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है ।
- **वर्ष 1950-70 के दशक में आय का वितरण**

अध्याय – 13
मुद्रास्फीति

- परिभाषा- वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में निरंतर बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहते हैं।
- मुद्रास्फीति हमारे बजट को प्रभावित करती है। इसके कारण किसी भी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है। वास्तव में मुद्रा के क्रय क्षमता में उत्पन्न इस कमी को ही मुद्रास्फीति कहते हैं।
- प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना ऐसे डाकू से की है जो कि अदृश्य रहता है।
- मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर पड़ता है। मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के पास अधिवर्ष होता है। जिसे किसी संपत्ति में निवेश किया जा सकता है। जैसे - मुद्रास्फीति के कारण उपभोग महंगा होगा। उस संपत्ति के मूल्य में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी जो कि मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को निरस्त कर देगी। चूंकि मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी को संबोधित करती है।
- हर वह मुद्रा जिसकी क्रय क्षमता शुन्य हो जाती है उसे परिचालन से बाहर कर दिया जाता है। वर्तमान में 50 पैसा वह न्यूनतम मूल्य की मुद्रा है जिसका भारत में वैधानिक प्रयोग किया जा सकता है। परंतु इसका प्रयोग ₹10 तक के भुगतान के उपभोग तक ही किया जा सकता है। यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़े तब ऐसी स्थिति में देने वालों को घाटा होता है। जबकि ऋणी को लाभ होता है।

मुद्रा की मात्रा	= वृद्धि
मुद्रा का मूल्य	= कमी
समग्र मांग	= वृद्धि
समग्र पूर्ति	= कमी
वस्तुओं का मूल्य	= वृद्धि

मुद्रास्फीति के प्रकार - कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. Demand push inflation (मांग प्रेरित मुद्रास्फीति)
2. Cost push inflation (लागत प्रेरित मुद्रास्फीति)
3. Structural inflation (संरचनात्मक मुद्रास्फीति)

Demand Push Inflation (मांग प्रेरित मुद्रास्फीति)

- यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता (मुद्रा की आपूर्ति) ज्यादा हो या तो आय में बढ़ोतरी के कारण अथवा बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति के कारण तब उपभोक्ता का उपभोग बढ़ता है। यदि इस बढ़ते हुए उपभोक्ता मांग की सही मात्रा में सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी।
- यदि मांग में बढ़ोतरी के कारण सकल मांग, सकल आपूर्ति को पार कर जाए तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में चूंकि रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते हैं। इस बढ़ते रोजगार के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
- मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आर्थिक संवृद्धी से भी संबंधित होती है क्योंकि बढ़ती हुई मांग उत्पादन को भी बढ़ावा देती है।
- किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर को कम करने का प्रयास किया जाता है। परंतु बेरोजगारी की दर उसी गति से कम की जाती है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण से बाहर ना कर दे।
- इसे NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) कहते हैं।

Cost Push Inflation (लागत प्रेरित मुद्रास्फीति)

- प्रत्यक्ष तौर पर मांग नहीं परंतु अप्रत्यक्ष तौर पर मांग होती है। यह मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न नहीं होती है।
- लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती

है। अर्थात कच्चे माल अथवा किसी भी अन्य प्रकार की लागत में बढ़ोतरी हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवा स्वतः महंगी हो जाती है। उदाहरण स्वरूप डीजल जो कि परिवहन एवं उत्पादन की प्रक्रिया में इंधन का एक प्रमुख स्रोत है, महंगा हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तु स्वतः महंगी हो जाएगी।

Structural Inflation (संरचनात्मक मुद्रास्फीति)

- यह किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं में कमी हो एवं इससे मुद्रा स्थिति उत्पन्न हो तब यह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है।
- संरचनात्मक मुद्रास्फीति जमाखोरी (Hoarding), व्यवसायिक समूह करण (Cartelization), कालाबाजारी (Black Marketing) इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है।

- **जमाखोरी (Hoarding)** - यदि एक व्यापारी अथवा बिचोलिया किसी वस्तु को उत्पादक से अत्यधिक मात्रा में खरीद कर उसे बाजार तक न पहुँचने से लंबे समय तक उस वस्तु को अपने गोदाम में रख ले, जिससे बाजार में उस वस्तु की कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाए। तब यह जमाखोरी कहलाती है।
- **व्यवसायिक समूह करण (Cartelization)** - किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मांग एवं आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। यदि इन वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर आपसी सहमति से मूल्यों में बढ़ोत्तरी कर दी। तब यह व्यवसायिक समूह करण कहलाता है।
- **कालाबाजारी (Black Marketing)** - यदि एक अनिवार्य वस्तु जिसे सरकार सस्ते मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। परंतु विक्रय वस्तु को बाजार में उच्च मूल्य पर बेच दे तब यह कालाबाजारी कहलाती है।

- भारत क्योंकि एक विकासशील देश है रोजगार के अवसरों के उत्पन्न होने के कारण मांग प्रेरित मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है।
- भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं में कमी के कारण संरचनात्मक मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि कच्चे माल अथवा अन्य संसाधनों की कमी के कारण लागत पर मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है।
- भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण की जिम्मेदारी RBI की है। परंतु आरबीआई मात्र मांग आधारित स्थिति को ही उचित रूप से नियंत्रण नियंत्रित कर सकती है। लागत प्रेरित एवं संरचनात्मक मुद्रा स्फीति पर का नियंत्रण नहीं होता है। अतः केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग के बिना मुद्रास्फीति का नियंत्रण संभव नहीं है।

दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति जिस दर से बढ़ती है उस आधार पर इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मुद्रास्फीति के प्रकार	दर
सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति (Galloping inflation)	10 – 20%
भागती हुई मुद्रास्फीति (Runaway Inflation)	100 – 200%
अति मुद्रास्फीति (Hyper Inflation)	1000%

मुद्रा संकुचन / अपस्फीति (Deflation) –

- यह मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक अर्थात् मंहगाई का विलोम है।
- अपस्फीति वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की अवस्था को दर्शाती है। ऐसा मुख्यतः दो परिस्थितियों में देखा जाता है।

  1. यदि सकल आपूर्ति सकल मांग को पार कर जाए
  2. यदि सकल मांग सकल आपूर्ति से नीचे चली आए
- सामान्यतः मांग में कमी तरलता में कमी के कारण एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होती है।

- जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुँच जाए जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं तब यह भी मांग में कमी को जन्म देती है।
- यदि देश की अधिकांश जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या हो जाए तब से भी मांग प्रभावित होती है।

पुनस्फीति (Reflation) Or संस्फीति

- जब निरंतर अपस्फीति के उपरांत वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज हो तब यह पुनस्फीति कहलाती है।

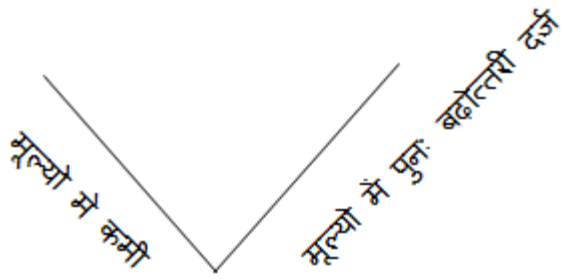

- पुनस्फीति / संस्फीति सामान्यतः आर्थिक मंदी के दौर में सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रदान किए गए बाह्य समर्थन से उत्पन्न होती है।
- मांग में कमी के कारण मूल्य नीचे जाते हैं। अतः मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करती है। जबकि सरकार कर में कटौती करती है। ऐसी स्थिति में मांग के साथ-साथ मूल्य में भी बढ़ोतरी देखी जाती है।

निस्पंद (Stagflation)

- स्टैगफ्लेशन (Stagflation) स्टैगफ्लेशन शब्द का निर्माण स्टैगनेशन व इन्फ्लेशन दो शब्दों को मिलाकर हुआ है । स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को इंगित करता है । जब मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी दोनों ही उच्च अवस्था में पहुँच जाती है । ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

मुद्रा प्रत्ययवस्फीति (Reflation)

- मुद्रा प्रत्यवस्फीति एक प्रकार से नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है । जब कभी मुद्रा अवस्फीति की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत नीचे गिर जाती है , तो सरकार कीमतों को फिर से पटरी पर लाने के लिए मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन करने लगती है , जिसे मुद्रा प्रत्यवस्फीति की अवस्था कहते हैं ।

Phillips Curve (फिलिप्स वक्र)

- ब्रिटिश अर्थशास्त्री फिलिप्स बेरोजगारी की दर (UR) एवं मुद्रास्फीति की दर (IR) के बीच के सामान्य संबंध को एक वक्र के माध्यम से दर्शाया। इस सामान्य संबंध के अनुसार बढ़ती बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति भी नीचे आती है। इस सामान्य संबंध का अनुपालन stagflation की दशा में नहीं होता।

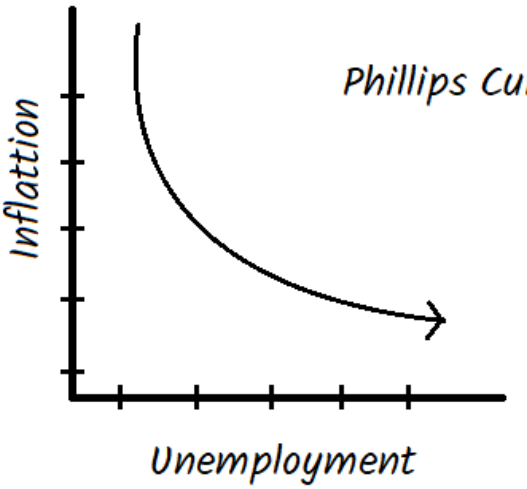

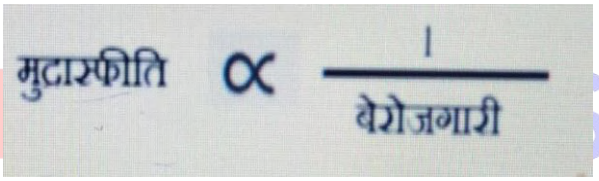

मुद्रास्फीति की गणना

भारत में मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य से दो प्रमुख सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है।

1. WPI (Wholesale Price Index/ थोक मूल्य सूचकांक)
2. CPI (Consumer Price Index/ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)

WPI अंतर्गत मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। जबकि CPI के अंतर्गत मूल्य में होने वाले परिवर्तन को खुदरा स्तर पर मापा जाता है।

WPI (Wholesale Price Index/ थोक मूल्य सूचकांक)

- WPI वर्ष 2013 के अंत में भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए सर्व प्रमुख सूचकांक रही है जबकि वर्तमान में वर्ष 2014 के बाद से Consumer Price Index/ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुख्य सूचकांक बना दिया गया है।

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत। अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिये पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है।

- **<u>मांग और पूर्ति प्रबंधन</u>**

मांग (Demand) एवं पूर्ति (Supply) अर्थशास्त्र में दो महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुएँ महँगी होती हैं एवं कुछ सस्ती होती हैं। कुछ बहुत कम मात्रा में होती हैं एवं कुछ बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। हम जब खरीदते हैं तो कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं तो कुछ महँगी। इनके भाव बदलते रहते हैं। ये मुख्यतः इनकी मांग एवं आपूर्ति के कारण होता है।

मांग क्या होती है ?

सामान्यतः मांग का अर्थ किसी चीज़ को पाने की चाह माना जाता है लेकिन अर्थशास्त्र में यह भिन्न है। इसमें मांग में पाने की चाह के साथ - साथ इसका मूल्य एवं इसका माप भी होता है। जैसे: आपको 5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल चाहिए। यह मांग मानी जायेगी।

परिभाषा (Definition of demand)

प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार "क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है।"

मांग के ज़रूरी अवयव :

कुछ ऐसे तत्त्व होते हैं जो यदि ना हो तो मांग केवल चाह बनके रह जाती है उसे हम मांग नहीं कह सकते हैं। अतः मांग कहलाने के लिए जिन तत्त्वों का होना ज़रूरी है वे निम्न हैं :

1. पाने की इच्छा : किसी चाह को मांग उपभोक्ता की इच्छा का होना होता है। यदि वह उपभोक्ता किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता है तो हम इसे मांग नहीं कह सकते हैं।

2. खरीदने की क्षमता : यदि कोई उपभोक्ता कोई चीज़ खरीदने की इच्छा रखता है तो उसके साथ ही उसके पास उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए अन्यथा वह मांग नहीं कहलाएगी। खरीदने का कोई साधन का होना आवश्यक है।

3. खर्च करने की तत्परता : किसी उपभोक्ता के पास चाह हो सकती है, साधन हो सकता है लेकिन यदि उसके पास खर्च करने की तत्परता नहीं है तो वह उसे खरीद नहीं पायेगा।

4. निश्चित मूल्य : इन सभी तत्वों के साथ - साथ एक वस्तु की मांग को बताने के लिए उसके साथ निश्चित मूल्य भी बताना होता है। जैसे हमें 2 किलो चीनी चाहिए तो हम बोलेंगे की 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी चाहिए।

5. निश्चित समय : ऊपर सभी तत्त्वों के साथ साथ एक निश्चित समय का भी होना ज़रूरी होता है। जैसे अभी उपभोक्ता को निश्चित वस्तु निश्चित समय में चाहिए या बाद में उसकी कुछ और पाने की चाह हो जायेगी। अतः निश्चित समय का भी ज्ञात होना ज़रूरी होता है।

मांग तालिका (Demand Table)

मांग तालिका एक या एक से ज्यादा उपभोक्ताओं द्वारा निश्चित समय में किसी वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर की गयी मांग की मात्रा के बारे में बताती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है :

1. व्यक्तिगत मांग तालिका
2. बाज़ार मांग तालिका

1. व्यक्तिगत मांग तालिका :

एक व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में की गयी वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग की मात्राओं की सूची होती है। जब हम इस तालिका को बनाते हैं तो इसमें बायीं तरफ हम वस्तु के विभिन्न मूल्य लिखते हैं एवं दायीं तरफ हम उपभोक्ता द्वारा की गयी मांग लिखते हैं।

तालिका

व्यक्तिगत माँग सन्तरे का मूल्य (प्रति इकाई रू. में)	सन्तरे की माँग (इकाईयों में)
1	90
2	80
3	70
4	60
5	50

ऊपर दी गयी तालिका में जैसा की आप देख सकते हैं एक तरफ विभिन्न मूल्य दिए गए हैं एवं वहीं दूसरी तरफ मांग की विभिन्न मात्राएँ दी गयी हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि शुरुआत में संतरे का मूल्य केवल एक रुपए प्रति इकाई था तब इसकी 90 इकाइयों की मांग थी लेकिन धीरे - धीरे यह मूल्य बढ़ा जिसके साथ यह मांग कम होती चली गयी। जब इसका मूल्य 5 रुपए प्रति इकाई पर पहुंचा तब इसकी मांग केवल 50 इकाइयों तक सीमित रह गयी थी। इससे हमें पता चलता है की एक वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है।

2. बाज़ार मांग तालिका :

एक बाज़ार मांग तालिका में किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीददारों द्वारा वस्तु की माँगी गयी मात्राओं के कुल योग की सूची होती है। जैसे मान लेते हैं की बाज़ार में केवल तीन खरीददार हैं। तो जो उन तीनों खरीददारों की विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग का योग होगा वही बाज़ार की मांग होगी। यह मांग ही बाज़ार की मांग होगी।

तालिका

संतरे की कीमत (प्रति इकाई)	वस्तु की मांग की मात्रा			बाज़ार में तीनों व्यक्तियों की कुल मांग
	A द्वारा	B द्वारा	C द्वारा	
1	90	70	170	330
2	80	60	160	300
3	70	50	150	270
4	60	40	140	240
5	50	30	130	210

जैसा की आप ऊपर दी गयी तालिका में देख सकते हैं हमें बाज़ार में केवल तीन ग्राहक दे रखे हैं अर्थात् बार में केवल तीन ही खरीददार हैं। जो इन तीनों खरीददारों की मांग का योग होगा जो सबसे दायीं तरफ दे रखा है वही बाज़ार की मांग होगी। यहाँ भी जैसा आप देख सकते हिं बढ़ते मूल्य के साथ बाज़ार की मांग भी कम हो रही है।

मांग वक्र (Demand Curve in hindi)

मांग की तालिका का रेखाचित्र रूप ही मांग वक्र कहलाता है। जब हम मांग की मात्राओं को रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे मांग वक्र कहा जाता है। निचे दिए गए रेखाचित्र में देखें :

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण

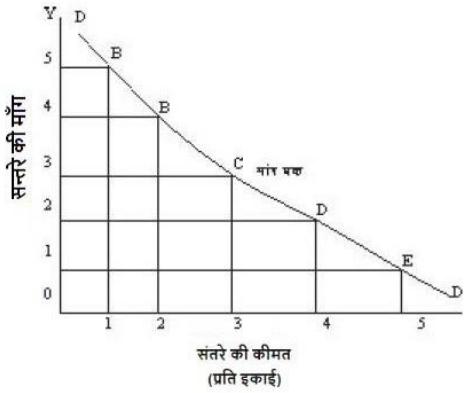

चित्र – माँग वक्र

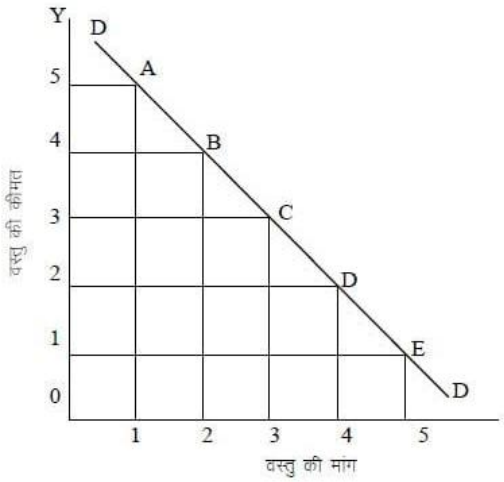

जैसा की आप देख सकते हैं हमने संतरे के मूल्य एवं मांग को रेखाचित्र पर अंकित किया है। x अक्ष पर मूल्य है एवं y अक्ष पर उसकी मांग है। यहाँ आप

2. विलासिता की वस्तुएँ : हीरे, सोने चांदी के जवाहरात आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिसे ऊंची प्रतिष्ठा वाले लोग ज़्यादा खरीदते हैं। यह मुख्यतः दिखावे के लिए प्रयोग किये जाते हैं। इन वस्तुओं की कीमत यदि बढ़ जाए तो लोग इसे खरीदना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि धनवान लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है । वे ही ऐसी वस्तुओं के मुख्यतः उपभोक्ता होते हैं। अतः यह भी मांग के नियम के अपवाद की स्थिति बन जाती है जब वक्र बढ़ती कीमतों के बावजूद नीचे की ओर नहीं जाता है।

3. दुर्लभ वस्तुएँ : दुनिया में कई ऐसी चीज़ें होती है जो कि मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं होती हैं। इनकी मात्रा बहुत सीमित होती है, जैसे दुर्लभ पत्थर । जो कि धरती के नीचे पाए जाते हैं। ये कभी - कभी खोजे जाते हैं एवं बहुत ज्यादा मँहगे होते हैं। इतनी अधिक कीमतों के बावजूद भी लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए खरीदते हैं। अतः ये वस्तुएँ भी मांग के नियम के अनुरूप काम नहीं करती हैं।

4. गिफिन वस्तुएँ : गिफ़िन वस्तुएँ ऐसी विशेष प्रकार की सुलभ वस्तुएँ होती हैं जिनका यदि मूल्य कम कर दिया जाए तो इसकी मांग भी कम हो जाएँगी एवं यदि इनका मूल्य बढ़ा दिया जाए तो इनकी मांग भी बढ़ जाएँगी । हम बाजरे का उदाहरण लेते हैं जब किसी व्यक्ति की आय कम हो जाती है तो वह गेहूं के मुकाबले बाजरा ज्यादा उपभोग करेगा क्योंकि यह सस्ता है एवं इससे बाजरे की मांग बढ़ जाती है। लेकिन यदि उसकी आय बढ़ जाती है तो वह बाजरे के मुकाबले गेहूं लेना पसंद करेगा जिससे बाजरे की मांग कम हो जायेगी। यह मांग के नियम के अपवाद की स्थिति बना देता है।

अभ्यास प्रश्न

1. मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें.....

(a) मुद्रा की कीमत घट जाती है
(b) मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है
(c) मुद्रा की कीमत पहले बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है
(d) मुद्रा की कीमत पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है **[A]**

2. मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(a) वस्तुओं की कीमतें घट जातीं हैं
(b) वस्तुओं की कीमतें बढ़ जातीं हैं
(c) कोई प्रभाव नही पड़ता है.
(d) पहले कीमतें घटती हैं फिर बढ़ जातीं हैं**[B]**

3. जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(a) कोई फर्क नही पड़ता है
(b) मुद्रा की पूर्ति घट जाती है
(c) मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है
(d) निम्न में से कोई नही **[C]**

4. बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की दशा में निम्न में से कौन सा वर्ग हानि में नही रहता है?

(a) उपभोक्ता वर्ग
(b) ऋण दाता वर्ग
(c) पेंशनभोगी वर्ग
(d) व्यापारी वर्ग **[D]**

5. निस्पंद (Stagflation) किसे कहते हैं?

(a) अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमे केवल मंदी मौजूद हो
(b) अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमे मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों एक साथ बनी रहें
(c) अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमे बेरोजगारी अधिक हो
(d) b और c दोनों **[D]**

6. मुद्रा स्फीति की तुलना डाकू से किसने की है?

(a) प्रोफेसर कीन्स
(b) प्रोफेसर जगदीश भगवती
(c) प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील
(d) अमर्त्य सेन और जे के मेहता **[C]**

7. "How to pay for Money" पुस्तक किसने लिखी थी?

(a) अमर्त्य सेन
(b) एडम स्मिथ
(c) कार्ल मार्क्स
(d) प्रोफेसर कीन्स **[D]**

व्यापारी, थोक विक्रेता, **प्रसंस्करणकर्ता**, इत्यादि) को अपने उत्पादन बेच सकेगा।

- बाजार की अनिश्चितता किसानों से उनके प्रायोजकों (sponsors) की तरफ विस्थापित हो जाएगी और साथ - साथ किसानों को बेहतर तकनीक एवं आगतों की भी आपूर्ति होगी (प्रायोजकों के माध्यम से)।
- विपणन की लागत घटेगी, जिससे किसानों का लाभ बढ़ेगा।
- किसानों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन किया जा सकेगा जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी जिस कारण किसानों के लाभ की मात्रा बढ़ेगी।
- इसके अंतर्गत किसानों की भूमि को उचित सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि की बिक्री, लीज या गिरवी ' रखने पर पूर्ण प्रतिबंध है तथा इनकी रिकवरी (recovery) के प्रति पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।
- विवादों को निपटाने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था की स्थापना, जिसमें स्पष्ट समय सीमा का प्रावधान किया गया है।

विशेषज्ञ के अनुसार इस अधिनियम के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत में कृषिगत उत्पादों के बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का विकास हो सकेगा। मजबूत आपूर्ति श्रृंखला न सिर्फ भारत के कृषि बाजार को वैश्विक बाजार से जोड़कर निर्यातोन्मुख करेगी, बल्कि किसानों को बेहतर तकनीक एवं सलाह उपलब्ध कराकर उन्हें उच्च मूल्य कृषि कार्यों के लिए भी प्रेरित करेगी।

2021-22 में कृषिगत सुधार

- आय को अधिकतम तथा जोखिम को न्यूनतम करना :- 3 नए कृषि कानून उन व्यापक आर्थिक सुधारों का एक पक्ष मात्र हैं जिनकी आवश्यकता भारतीय कृषि के स्थिरीकरण के लिए पड़ेगी।
- उदारीकृत खेती :- किसानों को अपने खेतों के लिए संसाधनों, भूमि, आदानों, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक रूपों के सर्वोत्तम मिश्रण का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए।
- कृषि संस्थानों और शासन प्रणालियों में सुधार :- केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों के बीच और केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना।

- ***भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ***

भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. आहार की आत्मनिर्भरता :- वैश्वीकरण द्वारा देश में विश्व बाजार से अपेक्षाकृत सस्ते खाद्यान्न का आयात हो सकता है और भारतीय किसानों का कृषि कार्य लाभकारी साबित हो सकता है। परिणामस्वरूप किसान लाभकारी कृषि उत्पादों की ओर आकर्षित होंगे और भारत अंततः अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए विश्व बाजार पर निर्भर हो जाएगा। इस प्रकार भारत द्वारा अर्जित की गई खाद्य आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। भारत के लिए इसके गंभीर राजनीतिक तथा नितिपरक परिणाम होंगे।
2. मूल्य स्थिरता :- यह भारत के हित में नहीं है कि वह कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए खासकर खाद्यन्नों की आपूर्ति के लिए विश्व बाजार पर निर्भर रहे। प्राकृतिक कारणों के कारण विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार - चढ़ाव की संभावना रहती है। इससे मूल्य स्थिरता को खतरा बना रहता है। अन्य देशों द्वारा अधिशेष कृषि उत्पादों की 'डंपिंग' की समस्या का भी सामना भारत को करना पड़ रहा है।
3. फसल प्रतिरुप :- फसल प्रतिरुप एक असंतुलित रूप ले सकता है जो पारिस्थितिकी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि किसान उन फसलों के उत्पादन के पक्ष में रहेंगे जिससे उन्हें अधिक लाभ हो। इन फसलों का चयन भूमि की उर्वरक शक्ति के विपरीत भी हो सकता है।
4. कमजोर वर्ग :- वैश्वीकरण का लाभ सभी क्षेत्रों, सभी फसलों तथा सभी लोगों के लिए एक समान नहीं होगा। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि किस क्षेत्र को, किस फसल को तथा किन लोगों को किस वर्ष में इससे कितना लाभ होगा। इसके अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लाभ बाजार पर आधारित होता है। पूंजी, निवेश तथा व्यवसायीकरण की कमी के कारण जो लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे उन्हें इससे कुछ लाभ नहीं होगा। वे शुद्ध उपभोक्ता या खरीदार होंगे। भारत में कमजोर वर्ग की जनसंख्या अधिक है (तीसरी दुनिया के देशों की तरह) जो अपनी आय

में वृद्धि नहीं कर सकते हैं न ही उन कृषि - उत्पादों को खरीद सकते हैं, जिनमें मूल्य स्थिरता नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि भारत का कमजोर वर्ग इस विकास से वंचित रह जाएगा। यह जरूरी है कि वैश्वीकरण का लाभ इन लोगों तक पहुंचे, यह समाज - अभिमुख लोक नीति द्वारा संभव है, जो एक बड़ी चुनौती है।

5. विश्व व्यापार संगठन संबंधी कटिबद्धताएं :- कृषि के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के प्रति भारत की कुछ समय निर्धारित बाध्यकर कटिबद्धताएं हैं जो लोगों तथा अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक हैं। इस चुनौती के दो पहलुओं को हम देखेंगे :

1.विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान के अनुसार कृषि क्षेत्र को सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट उसके सकल कृषिगत उत्पाद मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि भारत के लिए यह स्तर अभी 10% से कम है फिर भी आवश्यकता पड़ने पर इसे इस स्तर से नहीं बढ़ाया जा सकता। यह भारत के संप्रभु निर्णय के लिए एक खतरा है। इसके अतिरिक्त यदि किसानों की दी जाने वाली छूट को हटा लिया गया तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

2.दूसरी तरफ विकसित देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली छूट (अलग - अलग शीर्षकों के अंतर्गत) भारत जैसे देश के कृषि क्षेत्र के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। इन उच्च - स्तरीय कृषि छूटों का भी सामना भारत को करना पड़ रहा है।

RAS Mains गत वर्ष प्रश्न

प्रश्न.-1 भारत में उर्वरक अनुदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था क्या है ? (2018)

प्रश्न.-2 "कृषि अनुसंधान में वृद्धि से फसल व संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार हो सकता है" स्पष्ट कीजिए। (2022)

प्रश्न.-3 भारत में खाद्य प्रसंस्करण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ? इसके समाधान हेतु सरकारी योजनाओं पर विस्तृत लेख लिखिए । (2022)

प्रश्न.-4 भारत के कृषि क्षेत्र में परिवहन व विपणन की मुख्य समस्याओं को स्पष्ट करते हुए इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों पर लघु लेख लिखिए।

प्रश्न.-5 राष्ट्रीय जल नीति 2012 पर लघु लेख लिखिए।

प्रश्न.-6 जैव - उर्वरक क्या है ? वे भारतीय कृषि को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं ?

प्रश्न.-7. भारत में भूमि सुधारों की दिशा में किये गये प्रयास अत्यधिक धीमे रहे हैं । भारत में भूमि सुधारों की मंद प्रगति के कारणों की चर्चा कीजिए।

प्रश्न.-8. खाद्य प्रक्रमण इकाईयाँ गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक हो सकती है स्पष्ट कीजिए।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 16
औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां

औद्योगिक नीति का अर्थ

औद्योगिक नीति से तात्पर्य सरकार के उस चिंतन से है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। औद्योगिक नीति एक व्यापक धारणा है, जिसमें दो तत्त्वों का मिश्रण होता है।

- औद्योगिक विकास एवं संरचना के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण अथवा दर्शन क्या रहेगा ?

- इस दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिए, औद्योगिक इकाइयों को नियन्त्रित एवं नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं, नियमों और नियमनों को अपनाया जायेगा ?

  औद्योगिक नीति में उन सभी सिद्धान्तों, नियमों व रीतियों का विवरण होता है, जिन्हें उद्योगों के विकास के लिए अपनाया जाना है। यह नीति विशेष रूप से भावी उद्योगों के विकास, प्रबंध व स्थापना से सम्बन्धित होती है। इस नीति को बनाते समय देश का आर्थिक ढाँचा, सामाजिक व्यवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक व तकनीकी साधन व सरकारी चिंतन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

औद्योगिक नीति का महत्त्व

किसी भी राष्ट्र के उचित एवं तीव्र औद्योगिक विकास के लिये सुनिश्चित, सुनियोजित एवं प्रेरणादायक औद्योगिकी नीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व घोषित औद्योगिक नीति के आधार पर ही कोई राष्ट्र अपने उद्योगों का आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति किस प्रकार से महत्त्वपूर्ण होती है :

1. यह देश के औद्योगिक विकास को सुनियोजित कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है।
2. राष्ट्र को मार्गदर्शन व निर्देशन देती है।
3. सरकार को निश्चित कार्यक्रम बनाने में मदद करती है।
4. जनसाधारण को अपनी निश्चित जीविका का साधन बनाने में सहायता करती है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए औद्योगिक नीति बहुत प्रकार से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक विकास हो रहा है। देश में प्रकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन उनका उचित विदोहन नहीं हो रहा है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण पूँजी निर्माण की दर भी कम है तथा उपलब्ध पूँजी सीमित मात्रा में है। अतः आवश्यक है कि उसका उचित प्रयोग किया जाए। देश का संतुलित विकास करने कि लिए संसाधनों को उचित दिशा में प्रवाहित करने कि लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिए, एकाधिकार, संयोजन और अधिकार युक्त हितों को समाप्त करने अथवा नियंत्रित करने के लिए कुछ गिने हुए व्यक्तियों के हाथ में धन अथवा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए, असमताएँ घटाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने कि लिए तथा देश को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए एक उपयुक्त एवं स्पष्ट औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। वे क्षेत्र जहाँ व्यक्तिगत उद्यमी पहुँचने में समर्थ नहीं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाएँ और सरकार उनका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। साथ ही यह भी आवश्यक है कि निजी क्षेत्र का उचित नियंत्रण भी होना चाहिए जिससे कि विकास योजनाएँ ठीक प्रकार से चलती रहे।

भारत में औद्योगिक नीति का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में किसी औद्योगिक नीति की घोषणा कभी नहीं की गई, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था तथा उनकी नीति ब्रिटेन के हितों से प्रेरित थी और वह भारत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती थी। द्वितीय महायुद्ध के अनुभवों के बाद सरकार ने देश में औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की जिसके फलस्वरूप सन् 1944 में नियोजन तथा पुनर्निर्माण (Planning and Reconstruction) विभाग की स्थापना की गयी। इस विभाग के अध्यक्ष सर आर्देशीर दयाल द्वारा 21 अप्रैल 1945

2. अनार्थिक घटक (Non-Economic factors) : अनार्थिक बैठक में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है -

- सामाजिक घटक
- राजनीतिक घटक
- धार्मिक घटक

परीक्षोंपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक में तीन घटक- सकल घरेलू (GDP)उत्पाद की वृद्धि दर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग को शामिल किया जाता है।
- जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक(PQLI) का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्रमशः 100 तथा 1 होता है।
- राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक के परिकलन में उपभोग व्यय एवं शैक्षिक सूचकों का उपयोग करते हैं।
- शिक्षा विकास सूचकांक 2012-13 में उच्चतम रैंक पर लक्ष्यद्वीप एवं न्यूनतम रैंक पर झारखंड का था।
- मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्यप्रदेश था।
- मानव विकास सूचकांक(HDI) का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्रमशः 0 से 1 था।
- मानव विकास रिपोर्ट, 2019 में शीर्ष राष्ट्र में नॉर्वे का स्थान प्रथम है।
- मानव विकास रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। तथा सबसे निचले स्थान पर सोमालिया रहा।
- मानव विकास रिपोर्ट, 2019 में सबसे निचले स्थान पर नाइजर का नाम है।
- मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(UNDP) द्वारा जारी किया जाता है।
- पूंजी निर्माण के तीन आवश्यक घटकों में बचत, बचत के गतिशीलन हेतु वित्तीय संस्थाएँ तथा विनियोग को शामिल किया जाता है
- भारत में पूंजी निर्माण आँकड़ें एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- दीपक पारेख समिति आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से संबंधित है।
- औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पादन, परिवहन एवं संचार जैसी आधारभूत संरचना के विकास पर निर्भर करती है।

किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है।

RAS Mains गत वर्ष प्रश्न

प्रश्न.-1. औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। (2022)

प्रश्न.-2. 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किये गये। स्पष्ट कीजिए? (2022)

प्रश्न.-3. भारत में अवसंरचना ढांचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। (2022)

प्रश्न.-4. आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के विभिन्न मापक बताइये।

प्रश्न.-5. वैश्वीकरण को समझाइये?

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अध्याय – I
वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
2. विश्व बैंक
3. विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

वर्तमान स्वरूप - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 सदस्य राष्ट्रों वाला एक संगठन है जिनमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्त्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है।

इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्र अधिक शक्तिशाली हैं उस राष्ट्र के पास अधिक मताधिकार है।

इतिहास - इसका अस्तित्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयास में अनेक प्रयास विश्व भर में किये गये और मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने 1945 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की स्थापना की। इन दोनों के गठन के लिए 730 प्रतिनिधि देशों में 44 मित्र राष्ट्र देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के तरीके को निर्धारित करने के लिए न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में माउंट वाशिंगटन होटल में सम्मेलन के रूप में जमा हुए। ब्रिटेन वुड्स के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तावित विचार को सहमति दी थी कि मुक्त व्यापार ने वैश्विक समृद्धि और शांति को बढ़ावा दिया। वे आश्वस्त थे कि 1930 और 1940 के दशक में बड़े अवसाद का सामना करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ - उच्च शुल्क (टैरिफ), मुद्रा अवमूल्यन, भेदभावपूर्ण व्यापार गुट - के परिणामस्वरूप एक अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय वातावरण था। तब यह दृढ़ संकल्प था कि आर्थिक सहयोग शांति और समृद्धि प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विनिमय दरों को स्थिर करने और जरूरत वाले देशों को ऋण प्रदान करने में मदद करना है। संयुक्त शष्ट्र के लगभग सभी सदस्य आईएमएफ के सदस्य हैं, क्यूबा, लिचेस्टीन और अंडोरा जैसे कुछ अपवादों के साथ।

आईएमएफ के उद्देश्य

(i) वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना।
(ii) वित्तीय स्थिस्ता सुनिश्चित करना।
(iii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत् आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना।
(iv) दुनिया भर में गरीबी को कम करना।

आईएमएफ के भूमिका और कार्य

आईएमएफ के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है :

(i) अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग।
(ii) विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना।
(iii) भुगतान के संतुलन से निपटने में मदद करना और
(iv) सलाह और कर्ज देकर आर्थिक संकट से निपटने में मदद करना।

सामान्य गतिविधियों के रूप में आईएमएफ निम्नलिखित कार्य करता है :

(i) आर्थिक निगरानी (IMF निगरानी तंत्र): आईएमएफ सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तैयार करता है और कमजोरी / संभावित खतरे के क्षेत्रों का सुझाव देता है जैसे कि बड़े चालू खाते के घाटे / अधिशेष ऋण स्तरों वाली असंतुलित अर्थव्यवस्थाएँ। यह विचार आर्थिक असंतुलन के क्षेत्रों को उजागर करके 'संकट निवारण' पर काम करता है।

(ii) **वित्तीय संकट वाले देशों को ऋण (वित्तीय सहयोग प्रदान करना):** - आईएमएफ के पास 300 बिलियन डॉलर का ऋण देने योग्य धन है। यह उन सदस्य देशों से आता है जो निधि में शामिल होने के समय एक निश्चित राशि जमा करते हैं। वित्तीय/आर्थिक संकट के समय में, आईएमएफ वित्तीय पुनर्वितरण के हिस्से के रूप में ऋण उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो सकता है। IMF ने 1997 से अब तक 'बेलआउट' पैकेज में 180 बिलियन डॉलर से अधिक की व्यवस्था की है।

(iii) सशर्त ऋण / संरचनात्मक समायोजनः *ऋण देते समय, आईएमएफ आमतौर पर मिलने वाले कुछ मापदंडों पर जोर देता है, इसमें मुद्रास्फीति को कम करने (मौद्रिक नीति को मजबूत करना) की नीतियाँ शामिल हो सकती है । इन्हें 'सशर्तताएँ कहा जाता है ।*

(iv) तकनीकी सहायता और आंशिक प्रशिक्षणः *आईएमएफ कई रिपोर्टों और प्रकाशनों का उत्पादन करता है। वे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए समर्थन भी दे सकते हैं।*

(v) क्षमता विकासः *यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है एवं अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है । इस प्रक्रिया के एक भाग के रुप में यह निगरानी किसी एक देश के साथ - साथ वैश्विक स्तर पर भी की जाती है । IMF आर्थिक स्थिरता के संबंध में संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालने के साथ ही आवश्यक नीति समायोजन (NEEDED POLICY ADJUSTMENTS) पर भी सुझाव देता है।*

(vi) अन्य कार्य : *यह केंद्रीय बैंकों, वित्त मंत्रालयों, कर अधिकारियों एवं अन्य आर्थिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करता है । यह राष्ट्रों के सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाने, बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने, मजबूत कानूनी ढाँचे का विकास करने, शासन में सुधार करने में सहयोग करता है और वित्तीय आँकड़ों एवं व्यापक आर्थिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है। यह राष्ट्रों को सतत् विकाय लक्ष्य (SDG) की ओर प्रगति करने में भी सहयोग करता है।*

आईएमएफ का प्रशासन

बोर्ड ऑफ गवर्नरः इसमें एक गवर्नर एवं प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। प्रत्येक सदस्य देश अपने दो गवर्नर नियुक्त करते हैं। यह कार्यकारी बोर्ड के लिए कार्यकारी निदेशकों के चयन या नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है।

- *कोटा (QUOTA) वृद्धि, विशेष आहरण अधिकार के आवंटन का अनुमोदन करना।*
- *नये सदस्य का प्रवेश, सदस्य की अनिवार्य वापसी ।*
- *समझौते के अनुच्छेदों एवं उप-नियमों की शर्तों में संशोधन।*
- *मंत्री स्तरीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) और विकास समिति बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देती है।*
- *सामान्यतः IMF एवं विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्ष में एक बार बैठक होती है । बैठक के दौरान उनके संबंधित संस्थानों के कार्यों पर चर्चा की जाती है।*
- *मंत्रालय - संबंधी समितियाँः दो मंत्री स्तरीय समितियों द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह दी जाती है।*
- *अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC): IMFC में 24 सदस्य होते हैं जिन्हें 190 गवर्नर में से चुना जाता है और ये सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।*
- *यह समिति अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) के प्रबंधन पर चर्चा करती है ।*
- *यह समझौते के अनुच्छेदों में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा करती है।*
- *इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य सामान्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है।*

आईएमएफ का संचालन और कमियाँ

आईएमएफ कैसे वित्तपोषित होता है? आईएमएफ उन सदस्य देशों द्वारा वित्तपोषित है जो सदस्यता के समय धन का योगदान करते हैं। वे इसे अपनी सदस्यता के दौरान बढ़ा भी सकते हैं। IMF अपने सदस्य देशों से अधिक धन के लिए भी पूछ सकता है। आईएमएफ के वित्तीय संसाधन 1950 में लगभग 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2018 तक लगभग 300 बिलियन डॉलर हो गए हैं, जो इसके 183 सदस्यों के योगदान से प्राप्त हुआ है । यह प्रारंभिक राशि देश की अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर करती है। जैसे यूएस ने आईएमएफ के साथ सबसे बड़ी राशि जमा की। आईएमएफ में वर्तमान में यूएस के पास 16 प्रतिशत मतदान अधिकार है जो आईएमएफ मे जमा किए गए इसके कोटा को दर्शाता है । यूके में आईएमएफ के 4 प्रतिशत वोटिंग अधिकार है। IMF में वित्त भार आधारित मतदान प्रणाली है ।

आईएमएफ अपने 74 साल के इतिहास में दो अलग-अलग चरणों से गुजरा है। प्रथम चरण के दौरान, 1973 के समाप्ति पर आईएमएफ ने प्रमुख मुद्राओं के बीच सामान्य परिवर्तनीयता को अपनाने की निगरानी की । सोने के मूल्य से जुड़ी निश्चित विनिमय दो की एक व्यवस्था की निगरानी की;

अध्याय – 3

ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना

ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद - राजीविका (RGAVP)

RGAVP एक स्वायत्त संस्था है जिसे अक्टूबर, 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था । यह समिति, समाज पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है और स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है।

वर्तमान में, RAJEEVIKA द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं लागू की जा रही हैं: -

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP) जून, 2011 से 60 विभागों में कार्यान्वित की जा रही है।
- अप्रैल, 2013 से 9 विभागों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) लागू की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को अप्रैल, 2013 के बाद से चरणबद्ध तरीके से शेष विभागों में लागू किया जा रहा है।

राजस्थान में क्षेत्रीय विकास योजनाएं

मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान

यह परियोजना वर्ष 2016-17 में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालौर जिलों में प्रत्येक में एक ब्लॉक में कार्यान्वित की जा रही है सिरोही (पिंडवाड़ा) और जोधपुर (बालेसर) के दो नए ब्लॉकों को योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत, क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (SHG) का गठन किया गया है तथा इन्हे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक साख सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेव के निवास क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मेव समुदाय अलवर और भरतपुर जिले के 12 ब्लॉक में केंद्रित है। मेव अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए, राजस्थान सरकार मेवात क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए 1987-88 से एक विशेष विकास कार्यक्रम चला रही है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

केंद्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) के रूप में 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) पेश किया गया था। BADP केंद्रीय सरकार की नीतिगत पहल है । जिसके अनुसार सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास किया जाना है।

यह कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 ब्लाकों, में लागू किया जा रहा है। BADP के तहत, ज्यादातर फंड सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निवेश किया जाता है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान सरकार द्वारा 2004-05 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनः लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झलावाड़ , भरतपुर, कोटा और बूंदी) की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतें शामिल हैं ।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान का दक्षिणी मध्यवर्ती हिस्सा विशेष रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह हिस्सा जनजातीय क्षेत्र विकास (TAD) के तहत कवर नहीं किया जाता तथा स्थानीय रूप से "मगरा" नाम से जाना जाता है।

निवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए, 5 जिलों के 14 ब्लॉकों में 2005-06 से "मगरा क्षेत्र विकास अभियान" शुरू किया गया था। वर्तमान में यह उपरोक्त जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए जल विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई हैं।

गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना (GGJVY)

राज्य के सभी 33 जिलों में गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना 30.09.2014 को शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार सृजन, निर्माण और सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है । यह योजना राज्य द्वारा वित्त पोषित है और राज्य के ग्रामीण इलाकों में कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत "शमशान/कब्रिस्तान" की सीमा-दीवारों के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाएगा । अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, 70 प्रतिशत धनराशि और जनजातीय उप योजना (TSP) क्षेत्रों में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

विधान सभा के सदस्यो द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)

इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता की मूलभूत संरचना बनाने और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्थानीय जरूरत आधारित आधारभूत संरचना का विकास करना है । यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 2.25 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए सालाना कुल आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत अनुशंसित होना चाहिए । मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना (MJSY) के तहत कुल आवंटन का 25 प्रतिशत या कुल कार्यों का 25 प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम -

पंचायत स्तर पर ग्रामीण लोगों की शिकायतों का निपटान करने व ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए पंचायत शिवरों का आयोजन किया जाता है। "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविरों" 14 अक्टूबर, 2016 से शुरू हुए हैं।

मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY)

इस योजना में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि जैसे कई क्षेत्रों में चयनित गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के अतिरिक्त MAGPY गांवों और वहां के लोगों को दूसरों के लिए आदर्श बनाने के लिए उनमें लोगों की भागीदारी, लिंग समानता, महिला गरिमा, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा, स्वच्छता, स्थानीय स्वराज्य, पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन जैसे मूल्यों को पैदा करने का लक्ष्य है।

ग्राम पंचायत विकास की मूल इकाई है, विधान सभा के सदस्य (विधायक) इस योजना के प्रमुख अंग हैं।

ग्रामीण सड़कें:

राजस्थान राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, दो योजनाओं को लागू किया जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ (GGP) और केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)।

ग्रामीण गौरव पथ योजना (GGP)

ग्रामीण गौरव पथ परियोजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख सड़क निर्माण परियोजना है, राज्य की योजना के तहत 33 जिलों में लगभग 2,048 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करने की योजना है । यह परियोजना राजस्थान लोक निर्माण विभाग द्वारा लागू की जा रही है ।

गौरव पथ योजना की विशेषताएं:

- ग्रामीण गौरव पथ के तहत, गांव की सड़कों को मुख्य मेगा राजमार्गों से जोड़ा जाएगा।
- एक वर्ष में निविदाएं पूरी करने वाले ठेकेदारों द्वारा सीमेंट कंक्रीट सामग्री से सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा।
- गांव की सड़कों के अलावा, छोटे सीवर सिस्टम भी बनाये जायेंगे।
- राजस्थान के 33 जिलों के 9900 गांवों में से 2105 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) (केंद्रीय सरकार की योजना)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 25 दिसंबर 2000 को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दशा

- ग्राम पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर करवाने के संबंध में।

- **शपथ**

लेने वाले अधिकारी	**दिलवाने वाले**
सरपंच / वार्डपंच / उपसरपंच	पीठासीन अधिकारी
प्रधान / सदस्य/ उपप्रधान	B. D. O
प्रमुख / उपप्रमुख / सदस्य	कलक्टर

त्याग पत्र :-

देने वाला	**स्वीकार करने वाला**
सरपंच / उपसरपंच / वार्डपंच	खण्ड विकास अधिकारी
उपप्रधान / पंचायत समिति सदस्य	प्रधान
प्रधान / उपप्रमुख / जिला परिषद सदस्य	प्रमुख (जिला)
जिला प्रमुख	- संभागीय आयुक्त

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना

बिंदु	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
राजनीतिक प्रमुख	जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य	प्रधान व पंचायत समिति सदस्य	सरपंच व वार्ड पंच
वर्तमान संख्या	33	352	11341
प्रशासनिक प्रमुख	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	BDO	VDO
चुनाव पद्धति	जिला प्रमुख का चुनाव - अप्रत्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष	प्रधान - अप्रत्यक्ष सदस्य - प्रत्यक्ष	सरपंच – प्रत्यक्ष उप सरपंच – अप्रत्यक्ष वार्ड पंच - प्रत्यक्ष
त्याग पत्र	जिला प्रमुख - संभागीय आयुक्त व जिला परिषद सदस्य - जिला प्रमुख	प्रधान - जिला प्रमुख सदस्य - प्रधान	सरपंच व वार्ड पंच BDO

- **PESA Act :- panchayat extension to Scheduled Area Act - 1996**
- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम
- भूरिया समिति की सिफारिश पर आया वर्तमान में 10 राज्य में पांचवी अनुसूची के क्षेत्र आते हैं।
- उद्देश्य -

1. भाग 9 के प्रावधानों को आवश्यक संसाधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना।
2. जनजातीय लोगों को स्वशासन प्रदान करना।
3. भागीदारी लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केन्द्र बनाना।
4. पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप एक उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना।

- आदिवासी समुदायों की परंपरा और रीति-रिवाजों की रक्षा और संरक्षण के लिए वर्तमान में PESA Act भारत में 10 राज्यों में लागू है –

1. ओडिशा 2. झारखंड 3. मध्य प्रदेश
4. छत्तीसगढ़ 5. आंध्र प्रदेश 6. तेलंगाना

और लगभग 20,000 मास्क आर.के.वी.आई.बी. द्वारा खादी संगठनों के सहयोग से वितरित किए गए।

अभ्यास प्रश्न

1. भारत में राजस्थान में वर्ष 2019-20 के लिए सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का रहा ?
   a. बाजरा b. चना
   c. गवार d. तिलहन
   Ans. (a)

2. प्रचलित मूल्य पर पशुधन क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा
   a. 13.98 b. 23.98
   c. 03.98 d. 53.98
   Ans. (a)

3. प्रचलित मूल्यों पर दूध का उत्पादन पशुधन उत्पादों में कितने प्रतिशत रहा
   a. 111.07 b. 81.07
   c. 91.07 d. 102.07
   Ans. (b)

4. राजस्थान में कितने प्रतिशत भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है
   a. 52.58 % b. 62.58 %
   c. 72.58 % d. 82.58 %
   Ans. (a)

5. राजस्थान में बंजर भूमि का प्रतिशत–
   a. 20.84 % b. 40.284 %
   c. 10.84 % d. 50.384 %
   And. (c)

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया ?
   a. 2002-03 b. 2009-10
   c. 2008-09 d. 2007-08
   Ans. (d)

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई ?
   a. 2011-12 b. 2012-13
   c. 2016-17 d. 2015-16
   Ans. (c)

8. राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां है
   a. जयपुर b. सिरोही
   c. बांसवाड़ा d. जैसलमेर
   Ans. (a)

9. राजस्थान में चूरू, झालावाड़, सिरोही, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर जिले किस औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं
   a. A b. B
   c. C d. D
   Ans. (c)

10. राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है
    a. 52.86 b. 65.32
    d. 70.00 d. 51.23
    And. (c)

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS MAINS गत वर्ष प्रश्न –

Q1. राजस्थान में रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्क कहां पर स्थापित किये गये हैं?

Q2. रीको राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है स्पष्ट कीजिए?

Q3. राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों पर टिप्पणी दीजिए।

Q4. रुडा (RUDA) क्या है? समझाइये।

Q5. राजस्थान में औद्योगिक विकास कम हुआ है? स्पष्ट कीजिए।

Q6. राजस्थान में स्थापित चार विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का नाम लिखो? (RAS - 2012)

Q7. राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? (2012)

RAS गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-

(1) राजस्थान में जैव ईंधन ऊर्जा के स्त्रोत क्या हैं? (RAS - 2021)

(2) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए क्या रियायतें और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ? (RAS - 2012)

(3) राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की दृष्टि एवं प्रमुख उद्देश्यों को समझाइये? (2021)

(4) राजस्थान में स्थापित 'पार्टनरशिप ब्यूरो' के क्या उद्देश्य हैं? (RAS - 2018)

(5) राजस्थान में औद्योगिक विकास को समझाइये ?

अध्याय – 7

प्रमुख विकास परियोजनाएं

1. मुख्यमंत्री निः शुल्क निरोगी राजस्थान योजना :-

- शुभारम्भ : 1 मई 2022
- "मुख्यमंत्री निः शुल्क दवा योजना" और "मुख्यमंत्री निः शुल्क जांच योजना" की सीमाओं का विस्तार करने के लिए 1 मई 2022 से शुरुआत।
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित

निरोगी राजस्थान अभियान : -
शुरू 18 दिसम्बर 2019
उद्देश्य : राजस्थान के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निवारण के लिए इस योजना के तहत् मौसमी संचारी रोग, असंक्रामक रोग, प्रदूषण आदि पर नियंत्रण के प्रयास
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित

(3) शुद्ध के लिए युद्ध अभिमान :-
शुरू 26 अक्टूबर 2020
उद्देश्य : राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए। एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी खाद्य-सुरक्षा अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित ।

(4) मुख्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना :-
शुरू 1 मई 2021
यह योजना चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित ।
बजट 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किया गया ।
योजनान्तर्गत हॉस्पिटल में भर्ती के 05 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है ।
योजना का उद्देश्य :

(S6) राजीव गाँधी स्कॉलरशिप फॉर एकडेमिक एम्सीलेंस योजना – 2021 :-

शुरुआत : 5 अक्टूबर, 2021

उद्देश्य: राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के 150 विश्वविद्यालयों / संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु ।

इसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना के अनुसार 8 लाख रुपये से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 100 प्रतिशत भुगतान (अधिकतम रुपए 12 लाख वार्षिक) एवं 8 लाख रुपये से 25 लाख रुपये पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 50% भुगतान

(S7) जनजाति भागीदारी योजना :-

जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त, 2021 को की गई।

इस योजना में जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे।

योजना के तहत् रुपये 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, रुपये 10 लाख से अधिक और रुपये 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा 25 लाख से अधिक की स्वीकृतियाँ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएगी।

(S8) मुख्यमंत्री राजश्री योजना :-

- उद्देश्य : राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए।
- यह एक प्रमुख योजना है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है।
- इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित । जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएँ वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक / संरक्षक को 6 किश्तों में कुल रुपये 50,000 की राशि प्रदान की जाती है।

(S9) किसान कलेवा योजना :

- शुरुआत - 20 जनवरी, 2014
- उद्देश्य - राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियासती दर पर भोजन उपलब्ध करवाना ।
- भोजन की थाली का अधिकतम मूल्य रुपये 40 निर्धारित है, जिसमें से 35 कारण मंडी समिति द्वारा व 5 रुपये भोजन करने वाले द्वारा दिए जाएंगे ।

➢ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज -I

- शुरुआत - अप्रैल 2003 से जुलाई 2008 (अंतिम रूप से 30 जून 2010 को समाप्त)
- उद्देश्य:- वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना।
- वित्त पोषण -JICA (जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी)
- कुल लागत = 442.10 करोड़
- इसमें राजस्थान के 18 जिले, 2 जन्तु उद्यान एवं पारिस्थिति पर्यटन स्थलों का विकास किया गया
- यह परियोजना स्थानीय जनता की सक्रिय जनसहभागिता एवं साझा वन प्रबंध के माध्यम से क्रियान्वित की गई है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज :-

- वित्त पोषण / सहयोग = JICA
- समय = अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2021 (पूर्ण)
- उद्देश्य = JFM (Joint forest management) साझा वन प्रबंधन की प्रक्रिया से वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यो के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना ।
- इस परियोजना के अंतर्गत 15 जिले तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र आते हैं।

❖ बजट वर्ष 2023-24 के प्रमुख बिन्दु

राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 33 हजार 988 करोड़ 1 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां
- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख रुपये का राजस्व व्यय
- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये
- वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62 हजार 771 करोड़ 92 लाख जो GSDP का 3.98 प्रतिशत है।

19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का 'महंगाई राहत पैकेज'-

- लगभग **एक करोड़ NFSA** परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ **प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा Food Packet,** 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय
- लगभग **76 लाख परिवारों** को LPG गैस **Cylinder 500** रुपये में उपलब्ध, एक हजार **500 करोड़ रुपये** का व्यय
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना** में **100 यूनिट प्रतिमाह** तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को **निःशुल्क बिजली** ।

युवा विकास एवं कल्याण :

- नवीन **युवा नीति, 500 करोड़ रुपये** का **'युवा विकास एवं कल्याण कोष'**
- पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए **Special Task Force (STF)** का गठन
- **'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'** के अन्तर्गत **30 हजार विद्यार्थियों** को लाभ
- जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए **'विवेकानन्द यूथ हॉस्टल**
- **मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना** में **10 एवं 15 प्रतिशत margin money,** 100 करोड़ रुपये का व्यय
- अल्प आय वर्ग को स्वरोजगार के लिए **'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना', एक लाख युवा** लाभान्वित
- Startups व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का Rajasthan Venture Capital Fund
- जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में **Planetariums** का निर्माण
- **Bio Technology Policy - 2023,** जयपुर में **APJ Abdul Kalam Institute of Bio Technology** की स्थापना,
- जयपुर में **Rajiv Gandhi Aviation University,** कोटा संभाग में **Mining University**
- जयपुर में **Faculty Development Academy**
- **कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं** में बालिकाओं को **20 हजार स्कूटियों की संख्या को बढ़ाकर 30 हजार** किया जाएगा ।
- छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत **कक्षा 1 से XII** तक **निःशुल्क** शिक्षा
- दसवीं कक्षा **के 10 हजार विद्यार्थियों** हेतु Rajasthan Talent Search Exam (RTSE) Scholarship
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों** का आयोजन
- **27 नये खेल स्टेडियम, भरतपुर** में **स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स,**
- **कोलिडा - सीकर व बांसवाड़ा** में **फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा** में कुश्ती, **राजगढ़ - चूरू** में एथलेटिक्स तथा **बाड़मेर व सीकर** में **बास्केटबॉल अकादमी**
- **Rajiv Gandhi National Youth Exchange Programme** के तहत 10 हजार युवाओं को exposure visit, जिला एवं राज्य स्तरीय **युवा महोत्सव** का आयोजन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

- **मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना** में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से 10 लाख रुपये कर दिया गया ।
- जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में **साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स**
- **प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद** में सरकारी मेडिकल कॉलेज, **एक हजार करोड़ रुपये** की लागत
- जोधपुर में **Marwar Medical University,** 500 करोड़ रुपये की लागत
- आरएनटी मेडिकल कॉलेज, **उदयपुर में Centre of Excellence for Sickle Cell Disease** एवं मातृ विज्ञान संस्थान, **कोटा** में **Neuro Science Centre**

- चाकसू - जयपुर **Centre of Excellence in Panchkarma** खोला जायेगा।

सड़क सुरक्षा :

जिला स्तर पर **Road Safety Task Force,** Trauma Triage Protocol की प्रभावी अनुपालना

सामाजिक सुरक्षा :

- **Mahatma Gandhi Minimum Guaranteed Income योजना-**
- MNREGS एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में **125 दिवस प्रतिवर्ष** की रोजगार गारंटी,
- सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को **न्यूनतम एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन,** हर वर्ष **15 प्रतिशत** स्वतः वृद्धि
- **Gig Workers Welfare Board** की स्थापना, **200 करोड़ रुपये** का **Gig Workers Welfare and Development Fund**
- **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना'** में Hospitalised श्रमिकों को **7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन** सहायता
- 'इंदिरा रसोई योजना' का **ग्रामीण कस्बों** में भी विस्तार, संख्या बढ़ाकर **दो हजार,** 700 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय
- **'वाल्मीकि कोष'** की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये
- जोधपुर में **महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय** कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय
- **8 हजार आंगनबाड़ी एवं 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी** के नवीन केन्द्र, 320 करोड़ रुपये का व्यय
- **राजस्थान निःशुल्क "UNIVERSAL HEALTH CARE" उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य**

❖ **औद्योगिक विकास:**

- औद्योगिक क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य
- उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर व पचपदरा - बाड़मेर में Inland Container Depots ब्लू पॉटरी के लिए **जयपुर में Centre of Excellence,** अलवर एवं **पुष्कर-अजमेर** में **'ग्रामीण हाट'**
- रोडवेज (RSRTC) के बेड़े में **एक हजार नई बसें** Service Model पर शामिल
- **Rajasthan City Transport Corporation** का गठन, 250 Fast Electric Vehicle चार्जिंग
- जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित '3D City' परियोजना

पेयजल :

- जीवन मिशन में 11 हजार 255 करोड़ रुपये लागत की 3 वृहद् पेयजल योजनायें

ऊर्जा :

- बाड़मेर में **एक हजार 100 मेगावाट** का लिग्नाइट आधारित Power Plant लगभग 7 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण

वन एवं पर्यावरण:

- **राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP)** में **एक हजार 694 करोड़ रुपये की** लागत के विभिन्न कार्य
- नमवारामगढ़ - जयपुर में Integrated Resource Recovery Park

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

- **Rajasthan Literature Festival** का आयोजन
- जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के **जयपुर कला समागम** का आयोजन
- 100 करोड़ रुपये राशि का **लोक कलाकार कल्याण कोष व मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना**

कानून व्यवस्था :

- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत/वार्ड स्तर पर **महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान** केन्द्र
- 50 हजार **'महात्मा गांधी सेवा प्रेरक'**

सुशासन :-

- **Real Time Auto Service Delivery System- SWATAH (स्वतः)** लागू
- जयपुर में **Rajiv Gandhi Centre for IT Development and e-Governance**
- अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर RCAT केन्द्र
- **Rajasthan Logistical Services Delivery Corporation (RLSDC)** का गठन
- **Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules** बनाये जायेंगे
- **नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं** के जनप्रतिनिधियों के मानदेय / **भत्तों में 15 प्रतिशत की वृद्धि**

- कृषि बजट 2022-23 राज्य में पहली बार पृथक से कृषि बजट को समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान विचार के साथ प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2022-23 के लिए कुल कृषि बजट प्रावधान 78,938.68 करोड़ था।

	घटक	रुपये करोड़ में	कुल कृषि बजट का प्रावधान % में
1.	कृषि अनुदान	29862.09	37.83%
2.	कृषि साख	20270.00	25.68%
3.	आधारभूत संरचना विकास	11946.31	15.13%
4.	जोखिम प्रबंधन	4465.18	5.66%
5.	सामाजिक सुरक्षा	4217.25	5.34%
6.	प्रशासनिक गतिविधियाँ	3334.97	4.23%
7.	कृषि विपणन	3007.95	3.81 %
8.	कृषि, शिक्षा, अनुसंधान	988.92	1.25%
9.	कृषि आधारित अन्य गतिविधियाँ	846.01	1.07%

चित्र–2.5

कृषि बजट 2022–23

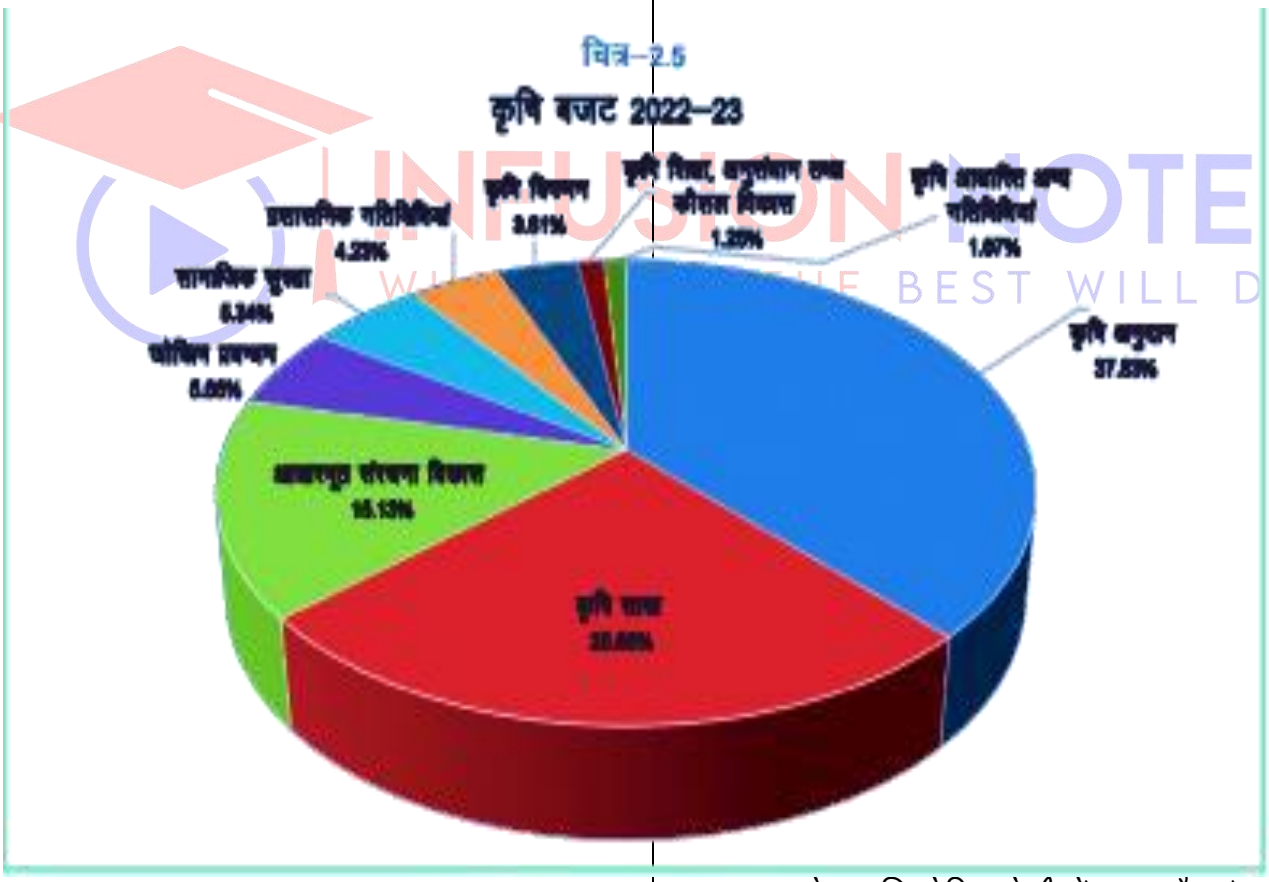

कृषक कल्याण कोष – गठन – 16 दिसंबर, 2019 (1,000 करोड़ रुपये)

जल संसाधन : भू जल : वर्ष 2022-23 में भू जल आँकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राज्य का 78% क्षेत्र अति दोहित श्रेणी में आता है एवं राज्य के कुल कुल भूजल दोहन की दर 150% है।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET (Graduation)-2023 - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

FREE SAMPLE

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Rajasthan CET Gradu. Level	07 Janu.2023(1st shift)	96 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/uwc5lp

Online order - https://bit.ly/3X6MGue

Call करें 9887809083